



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252917
CG-DL-E-13032024-252917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1203]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1265(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), इस विभाग के स्वायत्त निकायों के राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रही है जिसे नौ राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् (i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली (ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता (iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई (viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और (ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है;

और इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं/प्रसुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दिए जाते हैं;

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय अंतर्बलित हैं, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य राहत, सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को प्रसुविधा दी जाएगी, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु, कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –
 - (क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;
 - (ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;
 - (ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधा दी जा सकती है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (<https://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में लागू होगी।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1265(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department), in the Government of India is administering Support to National Institutes (hereinafter referred to as the Scheme) to autonomous bodies of this Department, which is being implemented through the nine National Institutes namely (i) Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi (ii) Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack (iii) National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata (iv) National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun (v) Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai (vi) National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Secunderabad (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai (viii) Indian Sign Language Research and Training Centre, Delhi and (ix) National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme other Services/ Benefits extended to the Persons with Disabilities (Divyangjan) according to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- (c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :-
 - (i) Bank or post office passbook with photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration card; or
 - (v) Voter identity card; or
 - (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
 - (vii) Kisan photo passbook; or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other document as specified by the Department;

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

- (c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department, through its Implementing Agency, shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administration.

[F.No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.